



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1316) पटना, बुधवार, 6 अगस्त 2025

सं0-35/रा०वि०आ०-01/2025-3640

वित्त विभाग

संकल्प

27 मार्च 2025

विषय:—षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 (एक वर्ष) के लिए विस्तारित करने के संबंध में।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सह पठित 243 (Y) के अनुपालन तथा बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1835 दिनांक 20.02.2019 द्वारा किया गया।

2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अंतरिम प्रतिवेदन जनवरी, 2020 में सौंपा गया तथा अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2021 को राज्य सरकार को समर्पित किया गया। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ वित्तीय वर्ष 2021-25 तक के लिए लागू हैं।

3. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो जायेगी। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने में लगभग एक वर्ष लगने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि समाप्त होने एवं सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान राशि का हस्तांतरण संभव नहीं हो पायेगा तथा अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित होगी। अतः इन कारणों से जो वित्तीय वर्ष 2021-25 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

4. समयक विचारोपरांत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 (एक वर्ष) के लिए विस्तारित किया जाता है।

5. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1316-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>